जा रही है, और कि इस योजना को इसके बाद जारी रखे जाने की संभावना है यदि हां तो कितनी अवधि के लिए; और

(ख) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कुछ और नई योजनाओं तथा प्रोत्साहनों की घोषणा करने का विचार रखती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के बजट में योजना को जारी रखने के लिये निधियों की व्यवस्था की गई है इस बीच इस प्रयोजन के लिए गठित अंतर मंत्रालय घोन समिति द्वारा इसकी जांच की जा रही है और उसमें संशोधन किया जा रहा है । इस समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है । इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस मामले पर कोई निर्णय लेगी :

Telep'bone Conncictions in Kerala

1979. SHRI THOMAS KUTHIRAV-ATTOM: Will the Minister of COM-MUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of telephone exchanges at present in Kerala;

(b) the total number of telephone connections as on 31st December, 1985, district-wise, in the State; and

(c) the total number of applicants in the waiting list as on date, category-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) The total number of telephone exchanges as on 1-2-1986 in Kerala is 573.

(b) The total number of telephone connections as on 31st December, 1965, District-wise, in the State is given in the attached statement.

(c) The total number of applicants in the waiting list as on 1.2.1986, category-wise, is given below: —

OYT	Non-OYT	Total
4229	65732	69961

statement

Sl. No.	Name of the District	Working Connections (31-12-85)
1	Trivandrum	19,164
2	Quilon	10,392
3	Pathanamthitta	4,877
4	Alleppay	8,7 2
5	Kottayam	13,193
6	Idukki	2,888
7	Ernakulam	27,932
8	Trichur	14,824
9	Palghat	7,771
10	Malappuram	4,715
11	Calicut	13,663
12	Winad	1,477
13	Cannanore	10,271
14	Kasaragod	3,571
	TOTAL	1,43,510

Use Of Chemicals in the Country

1980. SHRI THOMAS KUTHIRAV-ATTOM: Will the Minister of INDUS-TRY be pleased to state:

(a) the number of chemicals being imported [produced in the country;

(b) what are the effective ways in which Government can ascertain